

--: प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निवेद्याज्ञा :-

--: उपरिष्ठत अभिमापकगण :-

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. श्री जसपाल सिंह दहिया                  | -- प्रार्थी                 |
| 2. श्री मदन लाल पारीक                     | -- अप्रार्थी सं. 1 ता 4,5,7 |
| 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | -- अप्रार्थी संख्या 9       |

--: निर्णय :-

दिनांक:- 25/03/2026

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि-यह कि प्रार्थी का उक्त अगवान का दावा श्री मान जी के न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थी/वादी को कामयाबी की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस में संयुक्त एवं खातेदारान है। यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का ग्राम बड़ोपल वाराणी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073- वारतविक सम्वत् 2070 का खाता सं. 553/326 का खरारा सं. 2709/1231 की कुल 12.650 है. वाराणी 1 पुख्या आलाठी कृषि भूमि में से प्रार्थी व प्रार्थी न. 8 के नाम 5.060 है. वाराणी 1 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व प्रार्थी

सहायक कलक्टर एवं  
रूपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



पल बारानी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073-वास्तविक सम्वत् 2070 का खाता सं. 553/386 का खसरा सं. 2709/1231 की कुल 12.650 है. बारानी 1 कृषि भूमि को खातेदारी कृषि भूमि होने की घोषणा पाने का हकदार है। जो की जाकर उक्त 12.650 है. बारानी 1 कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज की जावे ।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के साथ सान्झा खाता में रखना नहीं चाहता है जिससे उक्त 12.650 है. बारानी 1 खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी एवं अप्रार्थी न. 8 को 5.0600 है. बारानी 1 खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 को ब. हिस्सा बराबर बराबर बंटवारा में दी जाकर अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जाने की घोषणा पाने की प्रार्थी हकदार है। जो की जावे एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिकी किया जावे।

कि प्रार्थी के खिलाफ अप्रार्थीगण ने एक गुट बना रखा है जो प्रार्थी से रजिस्ट्रार के पास प्रार्थी व के उक्त हक व हिस्सा को मारना चाहते हैं व रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करना चाहते हैं जबकि प्रार्थी की उक्त अनुसार कृषि भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 के नाम ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण नाजायज लीज व वंश गलत फायदा उठाने पर आमादा है एवं प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय करने पर आमादा है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि पर काब्ज काश्त वला आ रहा हैं। जिसे प्रार्थी खाता विभाजन में पाने के व उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के कानूनन हकदार हैं। जबकि खाता विभाजन वीर करवाये बिना ही अप्रार्थीगण प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने गलत मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होगी। जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। पृथम दृष्टया मामला व अपूर्ण्य क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की निशेधाज्ञा पाने का हकदार है कि अप्रार्थीगण ता फैसला प्रार्थना पत्र एवं खाता विभाजन से पहले उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त तमाम कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी व खिलाफ अप्रार्थीगण के निम्न प्रकार से स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के खिलाफ ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण ता फैसला दावा वाके तहसील पीलीबंगा का ग्राम बडोपल बारानी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073- वास्तविक सम्वत् 2070 का खाता सं. 553/386 का खसरा सं. 2709/1231 की कुल 12.650 है. बारानी 1 कृषि भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 के नाम दर्ज 5.060 है. ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें एवं रिकॉर्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें। व कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी ना करें।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 से 4, 6, 7 की और से निम्न प्रकार से है - यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई सम्भावना नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है परन्तु प्रश्नगत 12. 650 हैक. बारानी भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 8 के नाम 5.060 हैक. हिस्सा गलत दर्ज है। श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 के पक्ष में मुताबिक वसीयत



कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन मनगढ़त व मिथ्यारहित है स्वीकार नहीं। एवं अप्रार्थी सं. 5 व 8 आपस में एकराय है। इन तीनों को समस्त तथ्यों की एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पूर्ण जानकारी है। इस भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 का कोई हक हिस्सा नहीं है। इन द्वारा करवाया गया विधि विरुद्ध नामान्तरण भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त हो चुका है। ये इस भूमि के सह खातेदार व काशतकार नहीं है। ये इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी ने विना हक हिस्सा के हम अप्रार्थीगण को विरासतन प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु अनुतोष चाहा है जो विधि विरुद्ध होने के कारण प्रार्थी प्राप्त करने का हकदार ही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का वाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 व 8 के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुद्धा है। स्टेट जवाब वाद पत्र में लिया जाना अपेक्षित है।

बहस उभय पक्ष पर भलीभांती मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया प्रस्तुत दरतावेजों का अध्ययन किया गया प्रकरण में श्रीमान न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के यहां दो अपील पेश की गई जो दिनांक 16.01.2014 को स्वीकार की जाकर तहसीलदार पीलीबंगा के निर्णय को निरस्त करते हुए तथाकथित वसीयत को प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रभावहीन मानते हुए नामान्तरण सं. 1425 को निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश दिनांक 16.01.2014 के विरुद्ध प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 8 व नसीब कौर ने न्यायालय सम्भांगीय आयुक्त वीकानेर के यहां अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 18.08.2015 को खारिज हो चुकी है। इस प्रकार न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 16.01.2014 अन्तिम हो चुका है और नामान्तरण सं. 1425 निरस्त हो चुका है यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा के संबंध में राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त खाते के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते हैं उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पाबंद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है इस लिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मय अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रावली नंबर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 25/03/26 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।



(3)  
(जि. मिश्रा)  
सहायक कलेक्टर ए.आर.ए.एस.  
उपखण्ड प्रशासकीय अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर  
पीलीबंगा